जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 172 प्रभात जालोर, रविवार 28 सितम्बर, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, वांगचुक के आंदोलन की वीडियो सीमा पार भेजते हुए

अगर यह केवल अफवाह भी है तो भी भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण इस क्षेत्र में ''अस्थिरता'' पैदा हाने की संभावना के परिणाम स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितंबर। लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन एक स्थानीय आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, वह तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। कभी अपनी शांति और सहनशीलता के लिए मशहूर यह क्षेत्र अब हिंसक अशांति का गवाह बन रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये हालात भारत की सबसे संवेदनशील सीमा पर खतरे का मुकाबला करने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं।

भू-रणनीतिक विशेषज्ञ (जिओ स्ट्रैटजिस्ट) ब्रह्मा चेलानी ने कड़ी चेतावनी दी है कि लद्दाख में बढ़ती अस्थिरता सिर्फ एक आंतरिक शासन की समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत की सीमा रक्षा व्यवस्था, खासकर चीन के खिलाफ, को सीधी चुनौती है। चेलानी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, ''सन् 2020 से लद्दाख में भारत-चीन सीमा तनाव का केन्द्र रहा है।'' उन्होंने कहा, यहाँ की अशांति भारत की सामरिक तैयारी को कमजोर कर सकती है, जबकि यह इलाका देश की उत्तरी रक्षा पंक्ति का अग्रिम मोर्चा है।

- **चर्चा के साथ यह भी कहा जा रहा है कि वांगचुक चुपचाप पाकिस्तान भी गये थे और वांगचुक को विदेशी सहायता भी मिलती है, अपनी गतिविधियाँ जारी रखने के लिए।**
- **वांगचुक दूसरी ओर पुरजोर ढंग से कह रहे हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है तथा कोई विदेशी हाथ नहीं है। आंदोलन का आधार, केन्द्रीय सरकार के खिलाफ जनता में वादाखिलाफी की शिकायत घर कर गई है, जहाँ तक क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की बात है तथा स्थानीय जनता केन्द्रीय सरकार पर भावात्मक दूरी व अवहेलना बरतने का आरोप लगा रही है।**
- **लद्दाख, चीन के कब्जे में मौजूद अक्साई चिन तथा पाक अधिकृत भूमि के बीच में है तथा चीन भारत के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाकर जनता में असंतोष को हवा देता है। स्थानीय असंतोष अगर बढ़ जाता है तो जमीनी जानकारियाँ भारत के सुरक्षा बलों तक नहीं पहुँच पातीं तथा स्थानीय स्तर पर इंटैलिजैंस इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है।**

लद्दाख, जो चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन और पाकिस्तान अधिकृत इलाकों के बीच स्थित है, की स्थिति इसे एशिया का भू-राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील बनाती है। यहाँ कोई भी आंतरिक अस्थिरता भारत, चीन सीमा, ''लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर निगरानी रखने की क्षमता को कमजोर करती है, जहाँ के जमीनी हालात, 2020 में चीन की सेना की गलवान झड़पों के बाद से बदल चुके हैं। इसलिए यह अशांति केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है।

इस हफ्ते के विरोध प्रदर्शन, अधूरे राजनीतिक वादों, पर्यावरणीय क्षति और दिल्ली की कथित उपेक्षा के कारण भड़के हैं, जिसने लद्दाख की शांतिपूर्ण छवि को तहस-नहस कर दिया है। चेलानी के अनुसार, यह असंतोष खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा, ''लद्दाख की

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल शांति सम्मान

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितंबर। नोबेल समिति ने चुपचाप डॉनल्ड ट्रंप का नाम शांति पुरस्कार के दावेदारों की सूची से हटा दिया है।

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंड़ों के उल्लंघन और लगातार चली आ रहीं आपराधिक कार्यवाहियों का हवाला देते हुए, उनका नाम सूची से हटा दिया है।

- **नोबल कमेटी ने उनका नाम दावेदारों की लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि वे न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानदंड़ों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ अपराधिक कार्यवाहियां भी चल रही हैं।**

नॉर्वे, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के दिन, 10 दिसंबर को शांति पुरुस्कार प्रदान करता है। नोबेल शांति पुरुस्कार उन नोबेल पुरुस्कारों में से एक है, जो स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और हथियार निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से शुरु किया गया था।

इसके अलावा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा या चिकित्सा विज्ञान और साहित्य में भी नोबेल पुरुस्कार दिए जाते है।

सदा की भांति, रेल मंत्रालय बिहार पर नये प्रोजैक्ट्स की बारिश करने में मशगूल है

पर, विपक्ष भी पीछे नहीं है, रेल मंत्रालय की इन सौगातों की हवा निकालने में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। रेल बजट को 2017 में सामान्य बजट में मिलाने के बाद यह माना गया था कि रेल से जुड़ी लोकलुभावन राजनीति पर रोक लग जाएगी। लेकिन हुआ इसका उलटा। हर चुनावी राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले रेल परियोजनाओं की बौछार की जाती है। हरियाणा और महाराष्ट्र जहाँ इस साल के आरंभ में चुनाव हुये थे, के बाद, अब बिहार को भी इन दिनों कई बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की सौगात मिल रही है।

रेल और सड़क निर्माण एनडीए सरकार के विकास एजेंडे का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। इसी हफ्ते केन्द्रीय कैबिनेट ने इन दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं को कुल 6014 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड पर 78.94 किलोमीटर लंबा चार लेन हाईवे बनाने की योजना शामिल है। यह सड़क हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनेगी और पटना को बेतिया से जोड़ेगी।

बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट ने राज्य में 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाइन को डबल करने की भी मंजूरी दी। यह रूट कोयला, क्लिंकर, फ्लाई ऐश और सीमेंट जैसी वस्तुओं की माल ढुलाई के लिए अहम माना जाता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2192 करोड़ रुपये है।

- **प्रशांत किशोर, जिनका इस बार बिहार चुनाव में भाजपा विरोधी रुख है, केन्द्रीय सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गुजरात में एक के बाद एक इण्डस्ट्री लगाती जा रही है। पर, बिहार में गैर ए.सी. अमृत भारत रेल गाड़ियां शुरु कर रही है, जिससे बिहार का ''चीप लेबर'' अन्य विकसित राज्यों में जाकर भवन निर्माण आदि में काम करे, ये क्या सौगात हुई।**

इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें आठ नई ट्रेनों की शुरुआत भी शामिल है। इनमें नई बनाई गई ''अमृत भारत'' श्रेणी की ट्रेनें भी हैं। इनमें से पाँच लंबी दूरी की ट्रेनें बिहार के विभिन्न हिस्सों को नई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जोड़ेंगी, जबकि बाकी तीन ट्रेनें स्थानीय मार्गों पर चलेंगी। विपक्ष ने बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जबकि राज्य में एनडीए की डबल इंजन सरकार है। सबसे तीखी आलोचना जन सुराज नेता और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां गुजरात और दूसरे राज्यों में उद्योग लगा रहे हैं, वहीं बिहार के लिए नॉन-एसी अमृत भारत ट्रेनें शुरू कर सस्ते मजदूरों को दूसरे विकसित राज्यों में काम करने के लिये भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

लेकिन ऐसी आलोचनाओं का एनडीए सरकार की परियोजना, घोषणाओं पर कोई असर नहीं दिख रहा। इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट ने भागलपुर लाइन के मोकामा-मुंगेर

(शेष पृष्ठ 5 पर)

CMYK CMYK